1 करोड़ कीमत के चोरी हुए हीरे और सोने के आभूषण बरामद, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को दबोचा

बाहरी दिल्ली। दिल्ली में बाहरी जिला पुलिस की एंटी-ब्रैंचिंग सेल ने एक करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण चोरी करने के मामले में एक शातिर आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मूल रूप से सीतामढ़ी निवासी दीपक शर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर चोरी के आभूषण बरामद कर लिए है, जिनमें सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, अंगूठियां और लाकेट आदि शामिल है। पुलिस के अनुसार, करीब दो महीने पहले राज पार्क थाने में चोरी की एक बड़ी वारदात की शिकायत दर्ज कराई गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा शुरुआती छानबीन में कोई सुराग न मिलने के बाद मामले की जांच एंटी-ब्रैंचिंग सेल को सौंपी गई थी।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 241 ● नई दिल्ली ● सोमवार 13 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राजघाट पर बनेगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की समाधि के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उनकी समाधि राजघाट परिसर स्थित राष्ट्रीय स्मृति (राष्ट्रीय स्मृति स्थल) परिसर में बनाई जाएगी। प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हुआ था। वर्ष 2026 में दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) ने स्मारक के प्रारूप में कुछ डिजाइन संबंधी संशोधन सुझाए हैं, जिसे लेकर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संशोधित प्राथमिक प्रस्ताव डीयूएसी को सौंप दिया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया चल रही है। वहीं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समाधि के लिए बनाए गए ट्रस्ट से बजट मिलने का इंतजार कर रहा है। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से जुड़े पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता होंगे, जिनकी समाधि राजघाट परिसर में बनाई जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार उनकी समाधि राष्ट्रीय स्मृति परिसर में विकसित की जाएगी, जहां पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक बनाए जाते हैं। कांग्रेस शासनकाल में अलग-अलग समाधियां बनाने की परंपरा पर रोक लगा दी गई थी, जबकि बाद में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक बनवाए तथा अब प्रणब मुखर्जी की समाधि को भी मंजूरी दी है। राजघाट और उससे जुड़े स्मारकों का परिसर लगभग 245 एकड़ में फैला है। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी की समाधि से हुई थी। कांग्रेस शासनकाल में राजघाट पर अंतिम बार पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा की कर्मभूमि समाधि वर्ष 1999 में बनाई गई थी। इसके बाद अलग-अलग समाधियों की नीति पर रोक लगा दी गई थी। यहां यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व प्रधानमंत्री राव की समाधि बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा लगाई गई इस रोक को हटा दिया था।

मॉनसून सत्र- 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक, सरकार बताएगी विधायी एजेंडा; इन मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी में

नई दिल्ली । संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अधिकारियों के अनुसार, यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। संसद के प्रत्येक सत्र से पहले आयोजित होने वाली इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रखेंगे जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि सरकार का विधायी एजेंडा इस बार काफी व्यापक है और सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं, हाल के हफ्तों में कुछ विपक्षी दलों में सामने आए मतभेद और विभाजन के कारण सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल देखने को मिली है। पार्टी के 20 सांसदों ने ÷नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया÷ में विलय कर लिया है। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी की है। इसके अलावा, पार्टी के तीन सांसदों ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है।

विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा संसद में

शिवसेना (यूबीटी) में भी विभाजन हुआ है। लोकसभा में पार्टी के छह सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सांसद पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से नीट-यूजी पेपर लीक का मामला और ऑपरेशन सिंदूर में हुई हताहतों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है। कांग्रेस ने इस संबंध में रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है।

131 वां संविधान संशोधन बिल को फिर से ला सकती है सरकार

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा था कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का मॉनसून सत्र 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक बुलाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा था कि इस दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। उधर, प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अपनाने की उम्मीद है। इसके बाद समिति संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधेयक के एक प्रावधान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र अथवा राय सरकार के कोई मंत्री गंभीर अपराध के मामले में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से स्वतः हटाया जाएगा।

राम मंदिर चंदे की हेराफेरी पर पीएम मोदी चुप क्यों? कांग्रेस ने भाजपा-आरएसएस को घेरा

नई दिल्ली। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी पीएम के संरक्षण में हुई है। इस विश्वासघात के लिए देश भाजपा और आरएसएस को कभी माफ नहीं करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर चीज का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री जवाबदेही के वक्त चुप क्यों हैं? नए तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है।

क्या रसूखदारों को बचाने की हो रही है कोशिश?

जयराम रमेश का दावा है कि विशेष जांच दल भी रोजाना लाखों रुपये गायब होने की बात मान चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े गुनहगारों को बचाना चाहती है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि चंपत राय और अन्य ट्रस्टी कई गहरे राज छुपा रहे हैं। सरकार की ढिलाई से साफ है कि दोषियों को ऊपर से संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगामी संसद सत्र में उठाने का फैसला किया है। इसके लिए देश भर में 26 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी का यह मामला पहली बार सात जून को सामने आया था। एसआईटी की जांच और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई। मंदिर के चंदा संकलन और गिनती प्रक्रिया से जुड़े आठ आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। विपक्ष की चार मांगें- कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, फॉरेंसिक ऑडिट, जवाबदेही तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसने विपक्ष पर हिंदुओं को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस मुद्दे को शांत नहीं होने देंगे। विपक्षी दल संसद में प्रधानमंत्री से सीधे जवाब मांगेंगे। दूसरी तरफ, भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर निर्माण के समर्थक नहीं थे, वे आज इस पर राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन इस पर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है।

भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचा भाई, जंतर-मंतर पर दिया धरना

नई दिल्ली।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार (12 जुलाई) को भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया. भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी सैकड़ों समर्थकों के साथ जंतर-मंतर पहुंचे और इंसाफ की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.

अब तक किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई

धरने के दौरान चंदन तिवारी ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक किसी भी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. उनका कहना है कि परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है. उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा.

अमित शाह और पीएम मोदी से लगाई गुहार

चंदन तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की. उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर परिवार को न्याय दिलाएगी. उनका कहना है कि सरकार अगर बातचीत के लिए आगे आती है, तो परिवार अपनी बात विस्तार से रखने को तैयार है.

बातचीत नहीं होने तक जारी रहेगा धरना

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होती और उनकी मांगों पर बातचीत नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा. जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने की मांग दोहराई. फिलहाल इस मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

धरने के दौरान चंदन तिवारी ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक किसी भी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी,सीजेपी का आंदोलन 23वें दिन भी जारी

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 15वें दिन रविवार को शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत और बिगड़ गई तथा चिकित्सकों ने कहा कि उनका रक्तचाप और गिर गया है तथा उनका वजन 7.8 किलोग्राम घट गया है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर यहां जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) का विरोध-प्रदर्शन रविवार को 23वें दिन जारी रहा।

बुद्धिजीवी आंदोलन के प्रति दिखा रहे हैं समर्थन

कॉजपा की ओर से जारी स्वास्थ्य सूचना के मुताबिक, भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से वांगचुक का रक्तचाप गिरकर 104/66 एमएम एचजी (मिलीमीटर इन मर्करी) हो गया है, जबकि उनका वजन 7.8 किलोग्राम घट गया। इसके अलावा, कॉजपा ने बताया है कि कई नेता और जाने-माने बुद्धिजीवी आंदोलन के प्रति समर्थन दिखाने के लिए दिन में विरोध स्थल का दौरा करने वाले हैं।

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी

संगठन के अनुसार, केरल के पूर्व मंत्री के.के. शैलजा, के. एन. बालगोपाल और पी. राजीव प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज रविवार को सभा को संबोधित करेंगे। कॉजपा ने बताया कि दिन के कार्यक्रम का समापन बेरोजगारी का अर्थशास्त्र विषय पर अर्थशास्त्री जयति घोष के सार्वजनिक व्याख्यान के साथ होगा। यह व्याख्यान रोजगार के संकट और युवाओं पर इसके असर पर ध्यान केंद्रित होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन से जुड़े ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के सदस्यों - नेहा, मनीष, दीपक कुमार वर्मा और आमीन- ने विरोध स्थल पर एक अलग मंच पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी।

आधुनिक गांधी या कोई नायक

वांगचुक ने शनिवार को लोगों से दूसरों में नायक न खोजने की अपील की थी और कहा था कि वह सिर्फ एक आम नागरिक हैं, न कि आधुनिक गांधी या कोई नायक। उन्होंने एक्स पर वीडियो डालकर कहा था, कृपया किसी और में नायक न ढूंढें। अपनी जिंदगी के नायक खुद बनें। एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च में शामिल होने की अपील भी की।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है सीजेपी

उन्होंने कहा कि नागरिकों को एकजुट होकर सांसदों से परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए कहना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग कर रही है। कॉजपा ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की घोषणा की है।

सम्पादकीय...

व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष प्रयासों से मेरठ महानगर के निवासियों को जल्द ही आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत मेरठ समेत 18 प्रमुख शहरों में 1725 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से मेरठ की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को न केवल एक नई गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय यात्रियों को भी दैनिक आवागमन में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान समय में मेरठ में हो रहे तीव्र शहरीकरण और निजी वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण महानगर की यातायात प्रणाली पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद प्रभावी साबित होगा। नई ई-बसों के सड़कों पर उतरने से जहां शहरवासियों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा का बेहतरीन विकल्प मिलेगा, वहीं वायु प्रदूषण और जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में नगरीय परिवहन के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की यह नीति अत्यंत दूरदर्शी है। वर्तमान में नगर विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा प्रदेश के 15 नगर निगम क्षेत्रों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 700 बसें पहले से ही जीसीसी मॉडल पर चल रही हैं। इस सफल प्रयोग के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए अब सरकार ने मेरठ पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 9 मीटर और 12 मीटर श्रेणी की नई एसी ई-बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। परियोजना को धरातल पर पूरी दक्षता के साथ उतारने के लिए लोक-निजी सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया है। योजना के अंतर्गत चयनित निजी ऑपरेटर ही बसों की खरीद, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, योग्य चालकों एवं तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था तथा उनके पूर्ण संचालन व अनुरक्षण की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित कड़े प्रदर्शन मानकों के आधार पर ही ऑपरेटरों को शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यह संपूर्ण अनुबंध वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 12 वर्षों की लंबी अवधि के लिए प्रभावी होगा। इस बड़ी परियोजना को आर्थिक रूप से व्यावहारिक और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा भारी वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक 12 मीटर लंबी ई-बस पर 40 लाख रुपये तथा 9 मीटर लंबी ई-बस पर 35 लाख रुपये का आकर्षक अनुदान देने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, डिपो निर्माण के लिए आवश्यक भूमि संबंधित नगर निगमों द्वारा बिना किसी वित्तीय बोझ के पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बस किराया और अन्य प्रयोक्ता शुल्क का निर्धारण सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार का यह निजी निवेश आधारित मॉडल सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार लाएगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते निजी ऑपरेटर यात्रियों को समयबद्ध संचालन, बेहतर व्यवहार और अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

मेरठ में ई-बसों के इस बड़े विस्तार को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों का सफर सुगम होगा। यह संपूर्ण प्रयास उत्तर प्रदेश को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण और उनके उपयोग का एक प्रमुख हब बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। वैश्विक परिदृश्य में जीवाश्म ईंधनों की सीमित उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच, मेरठ जैसे तेजी से बढ़ते महानगर में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के अंतर्गत दिए जा रहे अभूतपूर्व लाभों से राज्य में एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में ये ई-बसें शून्य टेलपाइप उत्सर्जन सुनिश्चित करती हैं, जिससे महानगर में कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। आर्थिक दृष्टि से भी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग आम जनता और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए बेहद लागत प्रभावी साबित हो रहा है। पारंपरिक ईंधन की आसमान छूती कीमतों की तुलना में प्रति किलोमीटर परिचालन लागत बेहद कम होने के कारण यह उपभोक्ताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग के मासिक बजट को बड़ी राहत प्रदान कर रहा है, जिससे देश की वित्तीय स्थिरता को भी बल मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को तीन पहिया और चार पहिया निजी वाहनों पर भी भारी क्रय सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित (डीबीटी) होती है। इसके अलावा, प्रदेश में पंजीकृत होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर शत-प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की पूर्ण छूट जैसी क्रांतिकारी पहल की गई है, जिससे ग्राहकों पर पड़ने वाला प्रारंभिक आर्थिक बोझ काफी कम हो गया है। इस प्रकार सरकार हर स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सरकार चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार कर रही है। प्रमुख शहरी क्षेत्रों में हर तीन किलोमीटर पर और प्रमुख राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के मन से रेंज एंग्जायटी यानी चार्ज खत्म होने का डर पूरी तरह समाप्त हो सके। इसके साथ ही, राज्य में अल्ट्रा-मेगा बैटरी प्लांट और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना के लिए वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है, जिससे मेरठ सहित पूरे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। नगरीय परिवहन बेड़े में इन अत्याधुनिक ई-बसों के शामिल होने से मेरठ की जनता को एक ध्वनि-रहित, प्रदूषण-मुक्त और वातानुकूलित यात्रा का उत्कृष्ट अनुभव मिलेगा तथा यह महानगर आने वाले समय में देश के सबसे स्वच्छ और विकसित शहरों की अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा।

दलित, शोषित, पीड़ित और महिलाओं की आवाज़ हैं प्रबुद्ध विमर्श

प्रबुद्ध विमर्श पत्रिका के अप्रैल से जून-2026 अंक हमें प्राप्त हुआ इसके लिए संपादक श्री राजेश कुमार बौद्ध जी का बहुत बहुत आभार। जिनमें मेरी भी कविता पत्रिका में शामिल किया गया है-प्रबुद्ध विमर्श पत्रिका - राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है, पत्रिका वास्तव में दलित, शोषित, पीड़ित और महिलाओं की आवाज है। पत्रिका में प्रकाशित कुछ कविताएं, कहानी और लेखों को पढ़ा, उनके संदर्भ में मेरे विचार - प्रबुद्ध विमर्श पत्रिका के अप्रैल-जून 2026 अंक में प्रकाशित आपका सम्पादकीय पढ़ा। यह सच्चाई है कि आजकल संघी मानसिकता के लेखकों की भरमार हो रही है और यह दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के कार्यों और उनके साहित्य को नजरंदाज किया जा रहा है। भारत देश के आजाद होने के बाद से ही ऐसा साहित्य पढ़ा गया जिससे ब्राह्मणवाद की जड़ें मजबूत हों। इस सच्चाई से कोई इंकार नहीं किया जा सकता कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजनों को इकठ्ठा किया और उनमें स्वाभिमान जगाने का काम किया तभी वह खुलकर अपनी बात बोलने और लिखने लगे। आपके लेख में बिल्कुल सही कहा गया है कि अभी तक बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के विचारों और साहित्य को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ दलित लेखक ही करने का प्रयास कर रहे हैं वामपंथियों और सवर्ण समाज के लिए यह अभी भी अछूता ही है। बहुत ही सटीक सम्पादकीय है। बहुत बहुत हार्दिक मंगलकामनाएं। श्री ओ.जयप्रकाश कर्दम- सरकार बहरी है कविता के माध्यम से आम आदमी विशेषकर दलित बहुजनों के दर्द का बेहतर खाका खींचा है। अच्छी कविता है। श्री राजेश कुमार बौद्ध जी ने अपनी सार्थक कविता के माध्यम से एक गरीब आदमी के जीवन की वास्तविकता दर्शाते हैं। वास्तव में गरीब इंसान अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खुद के साथ-साथ अपने मासूम बच्चों को भी अबोध अवस्था से ही काम झेलना सिखा देता है। बहुत अच्छी कविता है। श्री बच्चा लाल उन्मेष जी ने अपनी कविता नायक के माध्यम से मान्यवर साहब कांशीराम जी के बारे में सही कहा है उन्होंने ही बहुजनों को जगाने का काम किया था लेकिन अब उनकी मेहनत को कुछ स्वार्थी लोगों ने बदनाम कर दिया। अच्छी कविता है। श्री हरिशरण गौतम जी की कविता भरोसा आजकल के माहौल में सटीक बैठती है। आजकल किसी भी व्यक्ति पर किसी को भरोसा नहीं है। लोगों को जहां भरोसा हुआ करता था वहां से भी अब भरोसा लोगों का टूटता जा रहा है। श्री रामचन्द्र प्रसाद त्यागी ने अपनी कविता मैं आदमी हूं के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि दलितों को कभी सवर्णों ने आदमी नहीं समझा भले दलितों ने कष्ट सहते हुए भी सवर्णों की सेवा की, लेकिन अब बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर जी के संविधान की बदौलत दलितों में भी स्वाभिमान जाग गया है। परन्तु मेरा ऐसा मानना है कि यह अभी आधा सच है क्योंकि दलित अभी भी पूरी तरह से जागा नहीं है, वह कहीं-कहीं सिर्फ मुंह से बकने लगा है जिसकी वजह से पिटता है। दलितों में एकता का सर्वथा अभाव है, वह एक-दूसरे की मदद के लिए कभी आगे नहीं आते। पढ़ाई में दलितों की स्थिति गांवों में बदतर होती जा रही है।

श्री जगदीश पंकज जी ने अपनी कविता,बाबा साहेब बोल रहे हैं के माध्यम से दलितों को जगाने और समझाने का काम किया है। अब दलितों और वंचितों को शिक्षित होकर अपने प्रति हो रहे अत्याचारों की लड़ाई एकजुटता से लड़नी होगी। बहुत अच्छी कविता है। डॉ. नीरा परमार जी ने अपनी कविता बाल मजदूर के माध्यम से उस बच्चे का चित्रण किया है जिसे बचपन से ही मजदूरी करने के लिए आगे कर दिया जाता है, कापी किताबों आदि पठन सामग्री से उसको कोई सरोकार नहीं। एक अच्छी कविता है। डॉ. एन सिंह जी ने अपनी कविता चेतावनी के माध्यम से तथाकथित सवर्णों को चुनौती देने का काम किया है,कि या तो तुम अब सुधर जाओ और हमें चैन से जीने दो वरना तो अंजाम ठीक नहीं होगा। श्री जितेन कुमार दास जी ने अपनी कविता घरेलू अंधेरा के माध्यम से यह बताया है कि जो दलित विदेशों में अच्छा काम करते हैं उन्हें ही अपने देश में नाकारा साबित कर दिया जाता है। दलित अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें जेलों में डाल दिया जाता कभी उपद्रवी तो कभी नक्सली बताकर। दलित अभी भी ब्राह्मणवादी वर्चस्व के शिकार है। एक बहुत अच्छी कविता है। डॉ. राधा बाल्मिकी जी ने अपने लेख,निर्गुण संत काव्य धारा की प्रवृत्तियां और कबीर का दार्शनिक चिंतन के माध्यम से संतों का बेहतरीन चित्रण किया है। वास्तव में संतों का लक्षण केवल निष्काम ,प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्ति ही नहीं, संत की कथनी और करनी में सामंजस्य भी होता है। संत कबीर अपने समय के एक श्रेष्ठ संत कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि एकदम अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने सामाजिक कुरीतियों चाहे वह हिन्दुओं में हो या मुसलमानों में जमकर विरोध किया। डाक्टर राधा बाल्मिकी ने संत कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय देकर अपने लेख को और अधिक सार्थक बना दिया है। एक बेहतरीन लेख है। मैडम अनीता भारती ने अपने लेख दलित महिलाओं पर बढ़ती हिंसा,व्यवस्थागत उपेक्षा और जातिगत सहिंसा राष्ट्रीय दलित महिला आयोग का गठन हो के माध्यम से सही कहा है कि दलित महिलाएं दोहरी मार झेलती हैं- एक तो ब्राह्मणवादी मानसिकता जो सभी महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती है और दूसरी दलित होना। दलित महिलाओं के इस उत्पीड़न को गहराई से समझना होगा और उनके निवारण के लिए कम से कम दलित पुरुषों को तो अपनी मानसिकता बदलने की अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि उनकी मांग सरकार से दलित महिला आयोग गठन करने की है जोकि बहुत दूर लगता है। बेहतर लेख! श्री विद्याराम कुढ़ावी जी ने अपने लेख बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन संवारने में चार महिलाओं का योगदान के माध्यम से उनकी बुआ, उनकी पत्नि, उनकी एक अभिन्न मित्र(फांसिस फिट्‌ज़गेराल्ड) और सविता अम्बेडकर के योगदान के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है। डॉ. पूरन सिंह साहब की कहानी मित्रता दो लंगोटिया यारों (अमर कुमार और कृष्ण कुमार) की एक बेहतरीन कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक निश्छल, निर्भय और सहृदय व्यक्ति एक निहायत ही स्वार्थी और मतलबपरस्त व्यक्ति (जोकि किसी और का तो छोड़ो अपने खास मित्र की तात्कालिक मदद नहीं कर सकता) का भी भला करने से पीछे नहीं हटता।

विदेश यात्रा

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल में की गई तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की यात्रा को निश्चित रूप से सफलतम व रचनात्मक कहा जायेगा क्योंकि उन्होंने तीनों देशों के साथ भारत के सम्बन्धों को प्रगाढ़ करते हुए नये आयाम दिये हैं और सुनिश्चित किया है कि हिन्द-प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र में स्थायी शान्ति को चुनौती न दी जा सके। श्री मोदी ने सबसे अन्त में न्यूजीलैंड की यात्रा की और वहां के प्रधानमन्त्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में यह तय किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद का कोई स्थान न रहे। हिन्द-प्रशान्त महासागर क्षेत्र के इन तीनों देशों में उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था है जिसके तहत इन तीनों देशों का निजाम चलता है जबकि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहा जाता है अतः बहुत स्वाभाविक है कि इन तीनों देशों के लोगों के बीच भी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता होगी। श्री मोदी ने इस मोर्चे पर भी नये रास्ते खोलने का प्रयास किया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्द-प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र में चीन जिस तरह अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन करता रहता है उसके प्रति भी श्री मोदी ने सर्वदा सन्तुलन बनाये रखने की अन्तर्दृष्टि का इजहार किया है। पूर्व में चीन ऐसी हरकतें करता रहा है जिसके प्रति इस क्षेत्र के देशों में आशंका रही है। इसी वजह से भारत उस क्वाड समूह का प्रमुख सदस्य है जिसमें जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। चारों देशों का यह गठबन्धन चीनी जवाब के रूप में भी देखा जाता है। इससे पहले भारत 80 के दशक तक यह मांग करता रहा था कि हिन्द महासागर क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाये परन्तु 90 के दशक के शुरू से जिस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण हुआ उससे भू-राजनीतिक गणित बदला और विभिन्न देशों के बाजार एक- दूसरे के लिए आकर्षण का केन्द्र बनते चले गये। सोवियत संघ का विघटन होने से वैश्विक सामरिक समीकरण बदलने लगे और आर्थिक समीकरणों की वजह से राजनीति भी बदलती गई। कम्युनिस्ट चीन देखते-देखते ही पूंजीवादी कम्युनिस्ट देश बन गया और बाद में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन बैठा। आर्थिक भूमंडलीकरण से भारत में भी परिवर्तन आया और आज यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत की इस ताकत का संज्ञान आज पूरा विश्व ले रहा है और इसके साथ विश्व के आधुनिकतम देश भी सहज कारोबार करने को लालायित हैं। अतः श्री मोदी अपनी हर विदेश यात्रा में भारत के उन क्षेत्रों में टैक्नोलॉजी सहयोग व विदेशी निवेश पर जोर देते हैं जिन्हें कुछ कमजोर माना जाता है या जिनमें और अधिक विस्तार की संभावना होती है। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया यात्रा में उन्होंने इस देश से परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु यूरेनियम ईंधन प्राप्त करने का करार किया और इंडोनेशिया को भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें देने का समझौता किया। वहीं न्यूजीलैंड के साथ कृषि क्षेत्र के डेयरी उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के आकलैंड हवाई अड्डे पर तो इस देश के प्रधानमन्त्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन उन्हें खुद लेने आये। इससे पता चलता है कि न्यूजीलैंड की निगाहों में भारत देश का कितना उच्च सम्मान है। मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 2014 में नागरिक ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु समझौता किया था। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ शान्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार था। श्री मोदी ने साफ किया कि अब वह क्षण आ चुका है। वैसे 2008 में जब भारत ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार किया था तो उसने वादा किया था कि वह भारत को परमाणु ईंधन सप्लाई करने वाले (एनएसजी) देशों के समूह का सदस्य बनाने के लिए अपने प्रभाव का हर संभव प्रयास करेगा।

बढ़ती ग़रीबी- पूंजीवाद, रोज़गार और इतिहास

अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध और उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जब ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हो रहा था, मशीन से बने मालों ने बहुत से दस्तकार उत्पादकों की जगह छीन ली थी। इसने लुड्डाइट आंदोलन को जन्म दिया, जो मशीनें लाए जाने का विरोधी था। बेरोजगारी बढ़ने के साथ, गरीबी के सापेक्ष आकार में बढ़ोतरी हो गयी, जैसा कि एरिक हॉब्सबाम ने एक अन्य इतिहासकार, आरएम हर्टवेल से एक बहस में तर्क दिया था। लेकिन, बाद में उन्नीसवीं सदी के दौरान हालात में सुधार हो गया। घोर गरीबी की मारी आबादी का अनुपात बढ़ना रुक गया और वास्तव में नीचे आ गया और ऐसा ही बेरोजगारी की मारी श्रम शक्ति के अनुपात के मामले में भी हुआ। ब्रिटेन के इस अनुभव का अक्सर पूंजीवाद की एक अंतर्निहित विशेषता के रूप में ही सामान्यीकरण कर दिया जाता है, कि हो सकता है कि शुरुआत में इससे गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़े, लेकिन अंततः औद्योगिक पूंजीवाद उन्हें नीचे ले आता है और इससे सबके ही जीवन स्तर में आम सुधार होता है, फिर चाहे इसमें आय की असमानता शुरुआत के समय के मुकाबले बढ़ ही क्यों न जाती हो। यह धारणा कि पूंजीवाद के विकास से अंततः अनिवार्य रूप से रोजगार में सुधार आता है तथा गरीबी घट जाती है, इतनी ज्यादा व्यापक रूप से फैली हुई है कि आम बेरोजगारी तथा घोर गरीबी के शिकार हरेक देश के लिए एक रामबाण उपाय यही सुझाया जाता है कि अपने यहां निवेश करने के लिए पूंजीपतियों को आकर्षित करो। और ठीक यही उपचार, भारतीय संघ में हरेक राज्य को भी सुझाया जाता है। यह करीब-करीब एक मानक मंत्र ही बन गया है कि, 'अगर तुम्हारे यहां गरीबी है, तो पूंजी को और बड़ी रियायतें दो, ताकि उसे लुभाकर अपने यहां ला सको और वह तुम्हें गरीबी से उबार उठा सके।' बहरहाल, इस धारणा के पीछे कोई सैद्धांतिक आधार तो खैर नहीं ही है, इसके अलावा यह इतिहास में वास्तव में जो कुछ हुआ था, उसके पूरी तरह से गलत समझे जाने को दिखाता है। अगर यह बस एक बार के लिए एक नयी मशीन लाए जाने का ही मामला होता, तब तो जब तक पूंजी स्टॉक के संचय की रफ्तार ऊंची बनी रहती और उसमें शिथिलता नहीं आती, तब तक तो यह सच होता कि मशीन के लाए जाने से शुरुआत में जो बेरोजगारी होती, आगे चलकर न सिर्फ उस कमी की भरपाई हो जाती बल्कि इस भरपाई से फालतू रोजगार भी पैदा हो जाता। लेकिन, औद्योगिक पूंजीवाद की पहचान तो अनवरत प्रक्रिया तथा उत्पाद नवाचारों या नयी खोजों से होती है। इसके कारण, श्रम के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया तो लगातार ही चलती जाती है। ऐसी स्थिति में इसका कोई कारण तो नहीं बनता है कि पूंजीवाद से पैदा होने वाली बेरोजगारी, अपरिहार्य रूप से गायब हो जाए। ऐतिहासिक रूप से भी इसका पूंजीवाद की किसी अंतर्निहित प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं है कि शुरुआत में इससे जो बेरोजगारी पैदा हुई थी, जिस पर लुड्डाइट इतने ज्यादा खफा थे, उसका बाद में शमन हो गया। ऐसा ब्रिटेन में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुआ था, जिसके तीन बिल्कुल स्पष्ट नजर आने वाले कारण थे। पहला था, ब्रिटेन से (और महाद्वीपीय यूरोप से) श्वेत नौबस्तियों वाले कम ठंडे इलाकों की ओर बड़ी संख्या में लोगों का उत्प्रवासन। अर्थशास्त्री डब्ल्यू आर्थर लेविस ने ध्यान दिलाया था कि जिसे 'दीर्घ 19वीं सदी' कहा जाता है (जिसमें पहले विश्व युद्ध तक का दौर शामिल कर लिया जाता है) उसके दौरान, पूरे पांच करोड़ यूरोपीयों ने कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका की ओर पलायन किया था। इन इलाकों में इन यूरोपीयों ने स्थानीय मूलवासियों को उनकी जमीनों से खदेड़ दिया, उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों के बाड़ों में बंद कर दिया और खुद यादातर खेतिहर बनकर बस गए। इस उत्प्रवास का पैमाना इतना बड़ा था कि अकेले ब्रिटेन में ही, 1814 से 1914 के बीच, उसकी आबादी में प्राकृतिक सालाना बढ़ोतरी का करीब-करीब आधा हिस्सा, वास्तव में इन 'नये इलाकों' के लिए पलायन कर गया था। इसने ब्रिटेन में बेरोजगारी के परिमाण में बहुत ही उल्लेखनीय पैमाने पर कम कर दी। इसमें योग देने वाला दूसरा कारक, उपनिवेशवाद का दूसरा उदाहरण था। हमारा इशारा इन नई बसाहट के उपनिवेशों (कॉलोनीज़ ऑफ सैटलमेंट) से भिन्न, जीत कर हासिल किए उपनिवेशों की ओर है। पूरी उन्नीसवीं सदी के दौरान और खासतौर पर उसके उत्तरार्द्ध में, मशीन से निर्मित उत्पादों का भारत जैसे विजय कर हासिल किए गए, उपनिवेशों में निर्यात किया जा रहा था। इन उपनिवेशों में ये पूंजीवादी उत्पाद, 'निरुद्योगीकरण' के नाम से जानी गयी प्रक्रिया के जरिए, स्थानीय पूर्व-पूंजीवादी उत्पादकों को प्रतिस्थापित कर रहे थे। इसका अर्थ यह था कि ये मशीन से उत्पादित माल अब ब्रिटेन में तो बेरोजगारी पैदा नहीं कर रहे थे (क्योंकि उनका निर्यात अब उपनिवेशों में किया जा रहा था), उल्टे उत्पादन में बढ़ोतरी के माध्यम से ब्रिटेन में घरेलू बेरोजगारी में कुछ कमी जरूर कर रहे थे। इन दो कारकों के अलावा एक तीसरा कारक और था। तीसरा कारक यह था कि शुरुआती चरणों में खुद मशीनों का उत्पादन भी बहुत ही श्रम सघन हुआ करता था। (इसी से मार्क्स की यह धारणा बनी हो सकती है कि पूंजी का आवयविक गठन--सी/ वी--प्रौद्योगिकी की प्रगति के जरिए हमेशा ही बढ़ोतरी पर रहेगा।) इसलिए, हालांकि मशीन-उत्पादित माल जीवित श्रम का एक हिस्सा प्रतिस्थापित कर रहे थे, आंशिक रूप से इसकी भरपाई इस तथ्य से हो जाती थी कि खुद मशीन के निर्माण में भी काफी श्रम को खपा लिया जाता था। बहरहाल, इन तीनों कारकों का, पूंजीवाद की किसी अंतर्निहित प्रवृत्ति से कोई लेना-देना नहीं था। पहले दो कारकों का संबंध सीधे-सीधे उपनिवेशवाद से था। यहां तक कि आखिरी यानी तीसरा कारक भी, जिसका संबंध खुद मशीन निर्माण के श्रम सघन होने से था, एक संयोग भर था; यह न तो पूंजीवाद की कोई अनिवार्य विशेषता था और न ही हमेशा के लिए सच था। इसका अर्थ यह हुआ कि यूरोप में पूंजीवादी उद्योग के विकास से आम तौर पर जो नतीजा निकाल लिया जाता है, उसकी कोई वैधता ही नहीं है। यह धारणा गलत है कि पूंजीवादी उत्पादन के विकास के क्रम में चाहे जितनी संक्रमणकालीन समस्याएं क्यों नहीं आयें और उसके लाभों का आबादी के बीच बंटवारा चाहे कितना ही असमानतापूर्ण क्यों न हो, यह अनिवार्यतः और अपरिहार्य रूप से सभी के भौतिक जीवन में बेहतरी लाता है। सच्चाई यह है कि यूरोप में जो कुछ हुआ, उसे उस दौर के विशेष संदर्भ ने ही संभव बनाया था। इसे पूंजीवाद के विकास का अपरिहार्य नतीजा नहीं माना जा सकता है। वास्तव में हम इससे और आगे भी जा सकते हैं। आज का पूंजीवाद ''विकास'' के एजेंडा के खिलाफ खड़ा हो गया है। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2010-20 के दशक के दौरान विश्व जीडीपी की सालाना वृद्धि दर, 2.6 फीसद रही थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दशकों में सबसे निचली वृद्धि दर थी। विश्व श्रम उत्पादकता की वृद्धि दर, जो दशक के पूर्वार्द्ध में 1.8 फीसद थी, उत्तरार्द्ध में घटकर 1.4 फीसद हो रह गयी थी। इसलिए, हम पूरे दशक का औसत 1.6 फीसद मान सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्व अर्थव्यवस्था में रोजगार की वृद्धि दर, जो उक्त दो आंकड़ों के अंतर के बराबर होगी, इस पूरे दशक के दौरान 1 फीसद सालाना के करीब रही होगी। लेकिन, इसी दौरान श्रम शक्ति में बढ़ोतरी की सालाना दर 1 से 1.5 फीसद के बीच रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दशक के दौरान कुल वैश्विक श्रम शक्ति में बेरोजगारी का सापेक्ष आकार, बढ़ रहा था। अगर हम विश्व अर्थव्यवस्था को समग्रता में देखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि नव-उदारवाद के महामारी-पूर्व के दशक के दौरान बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी। नव-उदारवादी पूंजीवाद में, जोकि पूंजीवाद का तात्कालीन चरण है, जीडीपी की वृद्धि दर में एक सुस्ती आती है।

एक तो इसलिए होता है क्योंकि यह पूंजीवादी विकास, असमानता को बढ़ा रहा होता है। दूसरे, ऐसा इसलिए भी होता है कि नव-उदारवादी पूंजीवाद के अंतर्गत, केन्सवादी कदमों के जरिए वृद्धि दर को ऊपर उठाने के लिए, राज्य के हस्तक्षेप के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए, नव-उदारवादी पूंजीवाद का अर्थ अनिवार्यतः यह होता है कि रोजगार वृद्धि भी सुस्त पड़ती है और वैश्विक श्रम शक्ति में वृद्धि की दर से नीचे भी चली जाती है। इस तरह, बेरोजगारों की फौज के सापेक्ष आकार में बढ़ोतरी, समकालीन नव-उदारवादी पूंजीवाद के अंतर्गत देखने को मिलने वाला एक तथ्य भर नहीं है बल्कि यह उसके साथ अनिवार्य रूप से लगा हुआ आता है। बेशक, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी देश बेरोजगारी तथा गरीबी से उबरने के लिए, पूंजीवादी रामबाण दवा को अपनाएंगे, सब के सब अनिवार्य रूप से विफल ही होंगे। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि इस पूंजीवादी रामबाण उपचार के जरिए, इन समस्याओं पर काबू पाने में जो भी देश सफल होंगे, वास्तव में अन्य देशों की कीमत पर ही सफल हो रहे होंगे। विकास के पूंजीवादी रास्ते पर चलते हुए, सभी देशों का अपनी जनता के बहुमत की बदहाली को दूर करने के अर्थ में ''विकास'' की ओर बढ़ना, असंभव है। वास्तव में इसका उल्टा ही सच है और चूंकि बेरोजगारों की फौज का सापेक्ष आकार ही गरीबी को तय करने वाला एक बड़ा कारक होता है, आज के समय में पूंजीवाद के रास्ते पर चला जाना अनिवार्य रूप से समग्रता में विश्व अर्थव्यवस्था में शुद्ध गरीबी को बढ़ाने का काम करता है। विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की बौद्धिक हाथ की सफाई यहां साफ हो जाती है। इस तथ्य के आधार पर कि कुछ देश पूंजीवादी विकास के रास्ते पर चलकर गरीबी का अपना बोझ उतारने में कामयाब हुए हैं।

2047 तक कृषि महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ भारत की कृषि व्यवस्था का भी मुख्य आधार स्तंभ माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर कार्य कर रही है। ''विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन'' के अंतर्गत राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक, तकनीक-संचालित, टिकाऊ और अत्यधिक लाभकारी बनाने का एक महा-संकल्प लिया है। डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों, सुशासन और दूरदर्शी विजन का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य को एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश की संभावित छह ट्रिलियन डॉलर की कुल अर्थव्यवस्था में अकेले कृषि क्षेत्र से एक ट्रिलियन यूएस0 डॉलर का योगदान सुनिश्चित करने का एक अभूतपूर्व और अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस विराट संकल्प को सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार संपूर्ण प्रदेश में नवाचार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है तथा जलवायु अनुकूल प्रजातियों को निरंतर विकसित कर रही है। इस ऐतिहासिक आर्थिक महा-लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डबल इंजन सरकार भूमि के कण-कण का प्रभावी उपयोग कर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान समय में प्रदेश की फसल सघनता जो वर्ष 2023-24 में 182 प्रतिशत दर्ज की गई है, उसे विजन 2047 के तहत बढ़ाकर 250 प्रतिशत तक करने का शानदार और प्रभावी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बेहतर सिंचाई प्रबंधन, वैज्ञानिक फसल नियोजन, गुणवत्ता युक्त कृषि निवेशों के सुचारू प्रबंधन और सर्वोत्कृष्ट नवीन तकनीकों को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने वर्ष 2047 तक खाद्यान्नों के बेहद सटीक और विशाल लक्ष्य तय किए हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर 550 लाख मीट्रिक टन और उसकी उत्पादकता 55 कुन्तल प्रति हेक्टेयर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार धान का उत्पादन लक्ष्य 320 लाख मीट्रिक टन और उत्पादकता 45 कुन्तल प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जबकि मक्के का उत्पादन 110 लाख मीट्रिक टन और उत्पादकता को 70 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाने की शानदार रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। प्रदेश सरकार तिलहन के उत्पादन को 63 लाख मीट्रिक टन व उत्पादकता 22 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा दलहन के उत्पादन को 57 लाख मीट्रिक टन व उत्पादकता 20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे राज्य में कुल फसलों का उत्पादन 1160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। धरती माता की उर्वरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, जिसके तहत मिट्टी में जीवांश कार्बन के स्तर को वर्तमान 0.8 से बढ़ाकर 1.0 तक करने का उत्कृष्ट लक्ष्य रखा गया है। इससे कृषि की उपज में भारी बढ़ोतरी होने के साथ-साथ दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर हरी खाद, कंपोस्ट और उन्नत जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार के भगीरथ प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश की 30 लाख हेक्टेयर बंजर व ऊसर भूमि का पूरी तरह से वैज्ञानिक उपचार करके उसे अत्यंत उपजाऊ और कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इस उपचारित भूमि पर दलहन, तिलहन व अन्य नकदी फसलों का प्रचुर उत्पादन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में बहुत बड़ा सुधार होगा। उत्तर प्रदेश की कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डबल इंजन सरकार इसे आधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस कर रही है। सरकार ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को आधुनिक कृषि मशीनरी से संतृप्त करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य में लगभग 75 प्रतिशत मशीनीकृत आधारित कृषि को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा।

किसानों की कार्यक्षमता और सुविधा को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक उपकरणों, ट्रैप प्लांटर्स और अन्य सटीक उपकरणों का समावेश किया जा रहा है और महिलाओं की भागीदारी सुगम बनाने के लिए वेंडर फ्रेंडली यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्री-टेक के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकार एआई, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग तकनीकों पर आधारित एक एकीकृत एग्री-डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इसके माध्यम से राज्य के किसानों को रियल-टाइम मौसम की सटीक जानकारी, प्रिसिजन फार्मिंग टूल्स और बेहतर निर्णय लेने वाली प्रणालियां आसानी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम आधारित सभी प्रकार की सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, जिससे खेती को सुरक्षित बनाया जा सके। तकनीक के इसी क्रम में एआई आधारित पार्टिसिपेटरी पेस्ट मॉनिटरिंग के माध्यम से समय पर फसलों का सर्विलांस करके किसानों को खरपतवार, कीट, रोग और किसी भी संभावित प्रकोप से बचाव की अग्रिम जानकारी और प्रभावी नियंत्रण उपाय प्रदान किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी को दोगुने से भी अधिक करने के लिए गन्ने की मुख्य फसल के साथ सहफसली खेती को अत्यंत प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक आधारित कृषि यंत्रों के प्रयोग से गन्ने के साथ-साथ सरसों, धनिया, मसूर, उड़द और मूंग जैसी फसलों की लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल पर अतिरिक्त खेती कराई जा रही है, जो किसानों की आय में सीधे तौर पर भारी वृद्धि कर रही है। राज्य की विभिन्न भू-जलवायु परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए सरकार आगामी पांच वर्षों के भीतर पांच भव्य बीज पार्क स्थापित करने जा रही है, जिसके बाद क्रमिक रूप से चार अन्य बीज पार्कों की भी स्थापना की जाएगी। बदलती वैश्विक और घरेलू मांगों के अनुरूप सरकार 20 प्रतिशत फसल विविधीकरण को लागू कर रही है, जिसमें मक्के के क्षेत्र को बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 'हर खेत में मेड़, हर मेड़ पर पेड़' के दूरदर्शी मंत्र के साथ कृषि वानिकी कार्यक्रम को एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप दे दिया है। इसके अंतर्गत तेजी से बढ़ने वाले और आर्थिक रूप से अत्यधिक मूल्यवान पौधों जैसे पॉपुलर, मिलिया डुबिया, ऑस्ट्रेलियन टीक, महोगनी और पाउलोनिया स्पीशीज का रोपण खेतों की मेड़ों पर कराया जा रहा है ताकि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सके। सरकार का परम लक्ष्य नवीनतम तकनीकों, उच्च मूल्य वाली चिया, रामदाना, क्विनोआ और मखाना जैसी फसलों की खेती को पांच लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करके किसानों की आय को तीन गुना करना है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों का व्यापक क्षमता विकास किया जा रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में 25 प्रतिशत की भारी कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का शानदार लक्ष्य है। प्रदेश के समस्त निजी नलकूपों को शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में भी सरकार पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने चन्दा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पॉकेटमिला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2014/[illegible])

वृक्षारोपण महायज्ञ- 2026 एक पेड़ माँ के नाम थीम पर पीएसी परिसर में हुआ वृक्षारोपण

फतेहपुर।

वृक्षारोपण महायज्ञ : 2026 एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर जनपद फतेहपुर में 12वीं वाहिनी पीएसी परिसर में राज्यमंत्री, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग उ0प्र0 सरकार कृष्णा पासवान, जनपद हेतु नामित नोडल अधिकारी/महानिरीक्षक निबंधन स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग, डा. सारिका मोहन, जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर हरिशंकरी(पीपल, पाखड़ व बरगद) के पौध रोपित कर वृक्षारोपण महायज्ञ की शुरुआत की। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, 12वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), उप सेनानायक, पुलिस क्षेत्राधिकारी आदि ने पौध रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का सन्देश दिया। वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के प्रोग्राम को

राज्यमंत्री, नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ व अन्य महानुभावों ने रोहित के पौधे वृक्ष धरा के आभूषण, इन्हें संजो कर रखने के लिए करें संरक्षण-राज्यमंत्री

एक पेड़ माँ के नाम थीम हमें हमेशा माँ की दिलाती याद- जिलाधिकारी

सम्बोधित करते हुए राज्यमंत्री कृष्णा पासवान ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम थीम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया है इसका उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौध रोपण अवश्य करना चाहिए और पौधरोपण के साथ-साथ देखभाल भी करनी चाहिए। कहा कि कोरोना काल में पौधों की महत्ता सबने देखी है,

इसलिए पौधरोपण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग जो पेड़ पौधे लगा गए है, उनका लाभ हमें प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, हमारे बुजुर्ग इन्हीं वृक्षों की फूल, पत्ती, जड़, तने से अपनी बीमारियां भी सही करते थे। कहा वृक्ष धरा का आभूषण है इसे संजोये रखने के लिए हमें पौधरोपण आवश्य करना चाहिए और उनकी देखभाल बच्चों की तरह करें, जब हम उनको बच्चों की तरह संभालेंगे तो पौधा अवश्य वृक्ष बनेगा। सभी जनपदवासियों से आग्रह किया कि सभी लोग पौधरोपण अवश्य करें और उनके संरक्षण का विशेष ध्यान रखें तभी वृक्षारोपण सार्थक होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 महाभियान की बधाई देते हुए कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अवश्य करना चाहिए और उसकी देखभाल भी करे। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन, शिक्षक दिवस आदि पर्वों पर भी एक पौध रोपित करें, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 अभियान में जनपद में लगभग 53 लाख पौध रोपित करने का लक्ष्य मिला है। जिसकी कार्ययोजना बनाकर सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुसार चिन्हित स्थलों पर पौध रोपित किए जा रहे है।

आंगनबाड़ी व स्कूलो में सब्जी व फलदार पौधे रोपित किए जा रहे है। मिशन 300 के तहत जो तालाब खोदे गए है, उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। सभी विभाग अपने लाभार्थियों के द्वारा भी एक-एक पौध का रोपण करा रहे है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम थीम हमें याद दिलाती है कि माँ हमेशा देने का काम करती है और वृक्ष भी हमें बहुत कुछ देते है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक-एक पौधा अवश्य लगाए और संरक्षण की भी व्यवस्था अवश्य करें। हमें आने वाली पीढ़ी को सुनहरा बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। हमें मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण का संतुलन बहुत जरूरी है। पौधरोपण के अभियान 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरुआत की गई थी, हमारे जीवन में किताबों और पौधों का बहुत महत्व है , हमें इसका ध्यान देना चाहिए। हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाए, तभी विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। इस मौके पर चित्रकला, पोस्टर, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले 04 छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में आए हुए नागरिकों एवं एनसीसी कैडेट के छात्र एवं छात्राओं को एक-एक पौध देकर सम्मानित किया गया। प्रभागीय निदेशक सामाजिकी एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर ने वृक्षारोपण महायज्ञ - 2026 महाभियान के तहत कराए जा रहे वृक्षारोपण को विस्तार से जानकारी दी ।

एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से जुड़ीं बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा, कार्यालय परिसर में किया पौधारोप

अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत रविवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. पूनम मिश्रा ने अपने कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डॉ. पूनम मिश्रा ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ-साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और मातृ सम्मान का प्रेरणादायी संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम में हरित वातावरण को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए सभी को प्रेरित किया गया।

बरेली को हराभरा बनाने की बड़ी मुहिम, बीडीए ने एक साथ लगाए 7,300 पौधे, जनप्रतिनिधियों ने भी थामा फावड़ा

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के 'एक पेड़ माँ के नाम' वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत शनिवार को बीडीए ने जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। बीडीए ने अपनी सभी आवासीय योजनाओं और विकास परियोजनाओं में 7,300 पौधों का रोपण कर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई मजबूती दी। अभियान के तहत सेक्टर-08 स्थित निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय परिसर में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया।

विधायक, एमएलसी और बीडीए उपाध्यक्ष ने किया पौधारोपण

वृक्षारोपण कार्यक्रम में बिथरी चैनपुर विधायक राघवेन्द्र शर्मा, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह और बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने संयुक्त रूप से पौधे लगाए। सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए जनसहभागिता को अभियान की सबसे बड़ी ताकत बताया। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम' केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मातृ सम्मान, प्रकृति संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।

विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए, संरक्षण का भी लिया संकल्प

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया, ताकि लगाए गए पौधे भविष्य में घने वृक्ष बनकर पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बना सकें। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा प्रदेश सरकार के हरित उत्तर प्रदेश अभियान को सफल बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जनसहभागिता आधारित कार्यक्रम भविष्य में भी लगातार चलाए जाएंगे। प्राधिकरण ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित रखने की अपील की।

अमृत वाटिका में हुआ वृक्षारोपण

'एक पेड़ माँ के नाम' वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के तहत कैंट विधानसभा क्षेत्र के मणिनाथ मंडल स्थित सुभाष नगर की अमृत वाटिका में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, वार्ड पार्षद, महानगर पदाधिकारी, मणिनाथ मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, देवतुल्य कार्यकर्ता समेत लोग मौजूद रहे। सभी ने पौधों के संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संकल्प लिया।

रामगंगा में कूदे प्रेमी युगल- 27 घंटे बाद युवक का शव बरामद, किशोरी की तलाश जारी

मुरादाबाद। कटघर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित रामगंगा पुल से नदी में छलांग लगाने वाले प्रेमी युगल में युवक का शव घटना के करीब 27 घंटे बाद रविवार को बरामद कर लिया गया, जबकि किशोरी का देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस, पीएसी और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कटघर के सूर्य नगर निवासी तुषार एक किशोरी के साथ बुलेट बाइक से रामगंगा पुल पहुंचा था। दोनों ने पुल पर बाइक खड़ी करने के बाद नदी में छलांग लगा दी थी। सूचना मिलते ही कटघर पुलिस, पीएसी और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और खोज अभियान शुरू कर दिया। रविवार को आधुनिक उपकरणों और स्टीमर की सहायता से नदी में व्यापक स्तर पर तलाशी ली गई। नदी का जलस्तर बढ़ा होने और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टीम ने मछरिया क्षेत्र समेत नदी किनारे कई संभावित स्थानों पर भी तलाश की। इसी दौरान दोपहर बाद तुषार का शव बरामद कर लिया गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, किशोरी की तलाश देर शाम तक जारी रही। पुलिस और पीएसी की टीमें लगातार नदी में सर्च अभियान चला रही हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है और उसे खोजने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश प्रधान का किया जायेगा भव्य स्वागत

मुरादाबाद।

आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद पर 19जुलाई को होने वाले जिला आर्य सम्मेलन की तैयारियों के लिये महानगर की आर्य समाजो की बैठक हुई जिसमें समस्त महानगर में सम्पर्क अभियान चलाने हेतु क्षेत्रानुसार जिम्मेदारी दी गयी। आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ, के प्रधान आचार्य स्वामी स्वदेश के प्रथम मुरादाबाद आगमन पर इम्पीरियल तिराहे पर पहले भव्य स्वागत किया जायेगा और तत्पश्चात वही से आर्यवीर दल के आर्यवीर मोटर साईकिलो से आगवानी करके आर्य समाज स्टेशन रोड पर लायेंगे जहां आर्यवीर सैनिक घोष के साथ कार्यक्रम स्थल तक ले जाने की योजना तैयार की गयी। इस अवसर पर ज्ञानेंद्र गांधी अजब सिंह आर्य डा अभय श्रोत्रिय डा राम मुनि डा अर्जुनवीर वर्मा, डा मनोज योगगुरु रमेश सिंह आर्य एडवोकेट, अरबिंद आर्यबंधु लोकेश आर्य रवीन्द्र आर्य रामसिंह निशंक, यशपाल आर्य प्राज्ञांशु आर्य दिनेश दीक्षित संतोष दीक्षित शास्त्री गायत्री जितेन्द्र आर्य, रमाशंकर आर्य दिनेश रस्तोगी आर्य, मयंक आर्य सूर्य प्रकाश द्विवेदी संदीप त्रिवेदी,शिवम् आर्य निहाल सिंह अमरनाथ आर्य आदि उपस्थित रहे।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जनआंदोलन बनाएं - भूपेंद्र सिंह चौधरी

मुरादाबाद। वृक्षारोपण महाअभियान-2026 के तहत गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय परिसर और कांठ मार्ग स्थित ग्राम कुचावली में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण का भी संकल्प है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश में 275 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और इस अभियान को जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह चौहान ने प्रत्येक नागरिक से हर वर्ष कम से कम पांच पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त ने पर्यावरण संरक्षण को जनस्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया, जबकि विधायक रितेश गुप्ता ने पौधों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया।मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने जल स्रोतों के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण और किसानों को उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने की बात कही। नोडल अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि वृक्षारोपण एक सतत जनभागीदारी का अभियान है। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि जनपद में इस वर्ष 24 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शादी के 16 दिन बाद नदी में मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

बरेली।

बिशारतगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता का शव रविवार सुबह गांव के पास नदी से बरामद हुआ, विवाहिता 9 जुलाई से लापता थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

थाना क्षेत्र के रघुवीपुरा निवासी नेत्रपाल ने बताया कि उन्होंने अपने 21 वर्षीय श्रीदेवी का विवाह 26 जून को बदायूं जिले के एक युवक के साथ किया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह मायके आ गई थी। मृतका के पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। इसी वजह से वह दोबारा ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बताया कि 9 जुलाई को नवविवाहिता बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। बाद में ग्रामीणों ने जानकारी

दी कि उसे गांव के पास नदी की ओर जाते हुए देखा गया था।

ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से मिला शव

सूचना मिलने पर पुलिस ने नदी और आसपास के क्षेत्र में खोज अभियान शुरू कराया। रविवार सुबह ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से नदी से विवाहिता का शव बरामद कर लिया गया।

शव मिलने की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। विशारतगंज प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की तहरीर और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

दस कदम, दस का दम: पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से भारत को क्या मिला? संबित पात्रा ने गिनाईं 10 उपलब्धियां

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राओं को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने रविवार को प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। इससे पहले वह सेशेल्स भी गए थे। इसी दौरान जापान के राष्ट्राध्यक्ष ने भी भारत का दौरा किया। पात्रा ने कहा कि इन यात्राओं से भारत को क्या हासिल हुआ, इसे आसान भाषा में समझाने के लिए, उन्होंने दस कदम, दस का दम के रूप में दस प्रमुख उपलब्धियां सामने रखीं।

भारत ने हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में क्या बढ़त हासिल की?

संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का सबसे बड़ा परिणाम हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करना रहा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समान सोच वाले देशों के साथ भारत की साझेदारी पहले से अधिक मजबूत हुई है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को नई दिशा मिली है।

रक्षा और समुद्री सुरक्षा में क्या नया हुआ?

उन्होंने बताया कि इन दौरों के दौरान रक्षा और समुद्री सहयोग को नई मजबूती मिली। समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे भारत की समुद्री क्षमताओं और सुरक्षा हितों को बल मिलेगा।

क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत को क्या फायदा होगा?

पात्रा ने कहा कि भविष्य की तकनीक और उद्योगों के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी महत्वपूर्ण सहमति बनी है। इससे भारत की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सकारात्मक प्रगति हुई है। इन समझौतों और सहयोग के माध्यम से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को अधिक सुरक्षित और स्थिर बना सकेगा।

अर्थव्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में क्या उपलब्धि मिली?

संबित पात्रा ने कहा कि आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाने को लेकर भी महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। विभिन्न देशों के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रगति हुई है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री को मिले विशेष सम्मान का क्या महत्व है?

उन्होंने कहा कि जिन देशों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, वहां उन्हें विशेष सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वागत मिला। पात्रा के अनुसार, यह केवल प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और विश्व मंच पर उसकी मजबूत होती साख का प्रतीक है।

सभ्यतागत और सांस्कृतिक रिश्तों को कैसे मिला नया आयाम?

पात्रा ने कहा कि भारत ने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और साझा सभ्यतागत संबंधों को भी नई ऊर्जा देने का काम किया। विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक सहयोग और पारंपरिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।

बंगाल में आज से लागू हो जाएगा गुंडादमन कानून

कोलकाता। बंगाल विधानसभा से हाल में पारित गुंडादमन कानून सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। असामाजिक गतिविधियों व गुंडों पर अंकुश लगाने के लिए बीते 29 जून को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में दो अहम बिल- पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 यानी गुंडा नियंत्रण कानून एवं पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया था। इसका उद्देश्य दंगों और अन्य तरह की हिंसा की रोकथाम करना है। दोनों विधेयकों को हाल में राज्यपाल आरएन रवि ने मंजूरी दे दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने

शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले के दौरे के दौरान घोषणा की थी कि सोमवार से यह दोनों कानून राज्य में लागू हो जाएगा। लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि ऐसे आरोपितों (असामाजिक तत्वों) को

बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत में रखने का कड़ा प्रावधान

बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक एहतियाती हिरासत में रखा जा सकेगा। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और गुजरात मॉडल पर बनाए गए इस कानून के तहत राज्य सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अधिकार मिलेगा, जिन्हें संगठित हिंसा, दंगा, तोड़फोड़ या अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल माना जाएगा। इस कानून के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को केवल जेल ही नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मुआवजा भी वसूला जाएगा और उनकी चल-अचल संपत्तियां भी जब्त की जाएगी। इस कानून के तहत दर्ज सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकेगी और आरोपितों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। इस कानून के तहत प्रशासन को अधिकार होगा कि वह किसी भी संदिग्ध शख्स की तलाशी ले, उसके दस्तावेज और संपत्ति जब्त करे और अपराध से जुड़ी चल-अचल संपत्ति को कुर्क या जब्त करे।

अगले साल से पटरी पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन- केंद्रीय रेल मंत्री

नई दिल्ली। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। केंद्रीय रेल मंत्री ने हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कहा, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना का पहला परिचालन खंड सूरत से बिलीमोरा के बीच अगले साल शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा, वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद, उसके बाद अहमदाबाद से ठाणे और अंत में अहमदाबाद से मुंबई तक का संचालन पूरा कर परिचालन शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के पूरा होने के बाद

कई प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। उनके अनुसार, पुणे और हैदराबाद के बीच सफर महज 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। वहीं, हैदराबाद से मुंबई की यात्रा लगभग 2 घंटे 50 मिनट, अमरावती की 1 घंटा 10 मिनट, चेन्नई की 3 घंटे और बेंगलुरु की 2 घंटे 35 मिनट में पूरी की जा सकेगी। तीन बड़े बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू होने के बाद हैदराबाद देश का एक प्रमुख हाई-स्पीड रेल हब बन जाएगा। वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए आवंटित 5,400 करोड़ रुपये का रेलवे बजट राज्य के रेल बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव का आधार बन रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के लिए तीन हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की योजना बनाई है, जिससे शहर का परिवहन और आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने कहा, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा गेम-चेंजर साबित होंगे। हैदराबाद एक प्रमुख हाई-स्पीड रेल हब के रूप में उभरेगा। इससे बड़े पैमाने पर विकास होगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं आपस में बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगी। इन तीन प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से तेलंगाना को भी बड़ा लाभ मिलेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों तथा कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

पीएम मोदी ने कतर के पूर्व शासक के निधन पर जताया शोक, सच्चे मित्र के रूप में किया याद

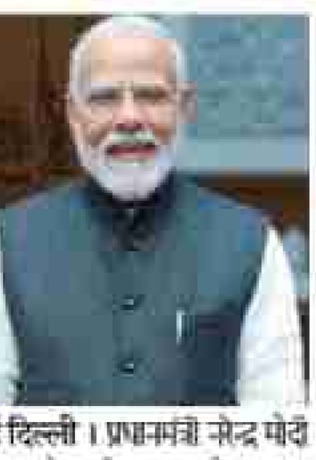

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर रविवार को शोक व्यक्त किया और उन्हें ऐसा दूरदर्शी नेता बताया जिन्होंने खाड़ी देश को विकास और समृद्धि की नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मोदी ने कहा कि भारत उन्हें एक सच्चे मित्र के रूप में याद करता है। सरकारी मीडिया के अनुसार, कतर के पूर्व शासक का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि की नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे मित्र के रूप में भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति मिले। शेख हमद ने कतर के शासक के रूप में फारस की खाड़ी के इस देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बनाया और बाद में अपने बेटे को सत्ता सौंप दी। शेख हमद ने 18 वर्ष तक अमीर रहने के बाद जून 2013 में पद छोड़ दिया था।

ईरान ने मिडिल-ईस्ट के 6 देशों पर हमला किया

अमेरिकी अटैक के जवाब में कार्रवाई; यूएस ने ईरान के 140 ठिकानों पर बम गिराए

नई दिल्ली।

मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन स्थित प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार, IRGC ने बयान जारी कर कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने एयरबेस पर स्थित अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर दिया।

इसके अलावा, MQ-9 रीपर ड्रोन रखे जाने वाले हैंगरों को भी निशाना बनाया गया। IRGC का कहना है कि यह हमला क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के जवाब में किया गया है। हालांकि, अमेरिका या जॉर्डन की ओर से फिलहाल इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही नुकसान का कोई आधिकारिक विवरण सामने आया है। यदि ईरान का यह दावा सही साबित होता है, तो यह जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाल के वर्षों के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाएगा। इससे पहले भी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन इस तरह बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का दावा स्थिति को और गंभीर बना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस घटना की पुष्टि होती है तो इससे मध्य पूर्व में संघर्ष और व्यापक हो सकता है तथा अमेरिका-ईरान के बीच सैन्य टकराव का खतरा और बढ़ जाएगा।

ओमान तट पर ईरानी हमला: 11 भारतीय नाविकों वाला जहाज बनाया निशाना, भड़का भारत का गुस्सा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ओमान के तट के पास व्यावसायिक जहाज GFS Gala×4 पर हुए कथित ईरानी हमले के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि जहाज पर मौजूद 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ओमान स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर खोज एवं बचाव अभियान का समन्वय कर रहा है। सरकार ने कहा कि लापता भारतीय नागरिक का पता लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। MEA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, हम ओमान के तट के पास व्यावसायिक जहाज GFS Gala&4 पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की सूचना है। हमारा दूतावास ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और बचाव अभियान पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत ने बचाव अभियान में सहयोग के लिए ओमान सरकार और स्थानीय अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मिशन प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत ने दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वैश्विक समुदाय की साझा जिम्मेदारी है और निर्दोष नागरिकों तथा व्यापारिक जहाजों पर हमले किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जा सकते।

पहलगाम में बादल फटा, सड़क बही, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड

जम्मू। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां मानसून की रफ्तार थमी है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है।यात जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद बाढ़ आई। कई खेत बर्बाद हो गए, सड़क बह गई। उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश के कारण लखवाड़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हुआ। कई गाड़ियां और मशीनें मलबे में दब गईं। इधर, देश के लगभग 70 हिस्से से मानसून के बादल गायब हो गए हैं। इसका कारण पाकिस्तान की ओर से आ रही सूखी हवाएं बताई जा रही हैं। मौसम की वेबसाइट ऑल इंडिया वैदर की रिपोर्ट के अनुसार ये सूखी हवाएं अरब सागर, मध्य भारत और दक्षिण भारत तक फैल गई हैं। इनकी वजह से राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना भी कम है।

शांत हुआ दतिया बवाल, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर बोले नरोत्तम-बीजेपी में ही जन्मा हूं और बीजेपी में ही मरूंगा

दतिया। दतिया में बीजेपी से टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा लगातार देखा जा रहा था,लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की है। नरोत्तम ने राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। लेकिन अब दतिया में होने वाले उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद शुरू हुआ सियासी हंगामा अब थमता नजर आ रहा है। रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की है। नरोत्तम मिश्रा नितिन नवीन के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। नितिन नवीन से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि वो न कभी नाराज थे, और न ही नाराज हैं और न ही कभी पार्टी से नाराज हो सकते हैं। उस दौरान वो पल भर का आवेश था और अब शांत हो चुका है। पार्टी बहुत ऊपर होती है और वो सब कुछ देखती है। इस मुलाकात में मिश्रा ने कहा कि वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे।

नरोत्तम बोले- भाजपा में ही जन्मा हू और भाजपा में ही मरूंगा

नितिन नबीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा एक और बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम ने कहा कि वो भाजपा में जन्मे हैं और भाजपा में ही मरेंगे। किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों पर भी उन्होंने विराम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा में ही मेरा जन्म हुआ है और मैं मरूंगा भी भाजपा में ही। नरोत्तम ने कहा कि वो उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।

आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर सबसे हमला, बोले- यह अब बाबर जनता पार्टी है

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने कहा, हम भगवान राम की रक्षा भाजपा से कर रहे हैं। भाजपा अब बाबर जनता पार्टी बन चुकी है। भाजपा कथित राम मंदिर लूट से देश का ध्यान भटकाने के लिए ही समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आइए यूसीसी पर उसके गुणों के आधार पर बहस करें, और हम इसका समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर में हुई इस कथित लूट की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं को लूटने वाले लोग इस समय सत्ता में बैठे हैं। आंदोलन के तहत उद्धव ठाकरे ने मध्य

मुंबई के दादर में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद मंदिर के बाहर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भगवा रंग का कुर्ता पहने उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि अगर कोई हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल करके मंदिर को लूटेगा, तो देश के हिंदू उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, -यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुओं को लूटने वाले लोग ही आज सत्ता में बैठे हैं। किसी भी लुटेरे से उसकी खुद की लूट की जांच करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह जांच पूरी तरह निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए।

काशी और मथुरा को लेकर जताई चिंता

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने राजनीति में मशहूर नारे अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा अभी बाकी है का जिक्र करते हुए गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अयोध्या के हालात देखकर अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि आगे चलकर काशी और मथुरा में क्या होगा। उद्धव ने कहा कि हम निडर, मासूम और देश से प्यार करने वाले हिंदू जरूर हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने हिंदुओं को जगाने का काम किया था, लेकिन आज की राजनीति में हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है।

स्टेटहुड पर सीएम उमर की हुंकार: बीजेपी पर लगाया बैक डोर पॉलिटिक्स का आरोप, 20 जुलाई से दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी देशभर में राजनीतिक दलों को कमजोर करने और सत्ता हासिल करने के लिए %बैक डोर पॉलिटिक्स% कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है। जम्मू में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी नेताओं का यह कहना भरोसे के लायक नहीं है कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कई राज्यों में राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम कर चुकी है। उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी को सीधे रास्ते से सत्ता नहीं मिलती, वहां वह पीछे के रास्ते से सत्ता में आने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह राजभवन से ही चलाना था तो फिर विधानसभा चुनाव कराने का क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी प्रक्रिया और केंद्र सरकार, संसद तथा सुप्रीम कोर्ट के आश्वासनों पर भरोसा किया था कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी से लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

20 जुलाई से दिल्ली में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन

उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर 20 जुलाई से दिल्ली में प्रदर्शन का नया चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को काफी समय दिया गया और करीब दो साल तक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अब पार्टी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। अगर अपने ही देश की राजधानी में अपनी मांग नहीं रखेंगे तो फिर कहां जाएंगे? उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल केंद्र

सरकार से किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लगाए वादा टालने के आरोप

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के बाद 18 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, जबकि बीजेपी लगातार बहाने बना रही है। उन्होंने मांग की कि बीजेपी स्पष्ट करे कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस दिया जाएगा। वहीं, खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से न सिर्फ जम्मू-कश्मीर मजबूत होगा, बल्कि देश भी और मजबूत होगा।

बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, उमर से आत्ममंथन की अपील

उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ किसी भी गतिविधि में विश्वास नहीं करती।

सक्षम भारत

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।